DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS Hindustan Times

NEW DELHI
SATURDAY
MARCH 25, 2023

Cycle track from Moti Bagh to Raisina Hill likely by 2024

Paras Singh
paras@hindustantimes.com

NEW DELHI: The New Delhi Municipal Council (NDMC) will soon start developing a bicycle track connecting New Moti Bagh near Ring Road with North and South Block on Raisina Hill as part of a ₹6.5 crore project to promote cycling in the New Delhi area, officials aware of the matter said.

The civic body received the approval from the Unified Traffic and Transportation Infrastructure (planning and engineering) Centre (UTTIPEC), the infrastructure planning arm of Delhi Development Authority (DDA), in January; it plans to complete the project in 12 months.

According to the approval granted by the agency, a copy of which was seen by HT, the longest contiguous bicycle track in the city will start from North-South Block and pass key government offices and government housing colonies.

NDMC vice-chairman Satish Upadhyay said that the track will also incorporate the 2.7km-long bicycle track being developed along the periphery of Nehru Park in Chanakyapuri. On January 16, lieutenant governor (LG) VK Saxena laid the foundation stone of the project to develop a modern cycling track along the 75-acre park located in the diplomatic enclave.

Upadhyay said there is a need to encourage the use of bicycles as an environment-friendly mode of transportation.

The 10km-long cycle track will cross 12 major roundabouts in the New Delhi area with a series of dedicated cycle tracks, shared lanes (with footpaths), cycle crossings, and parking bays.

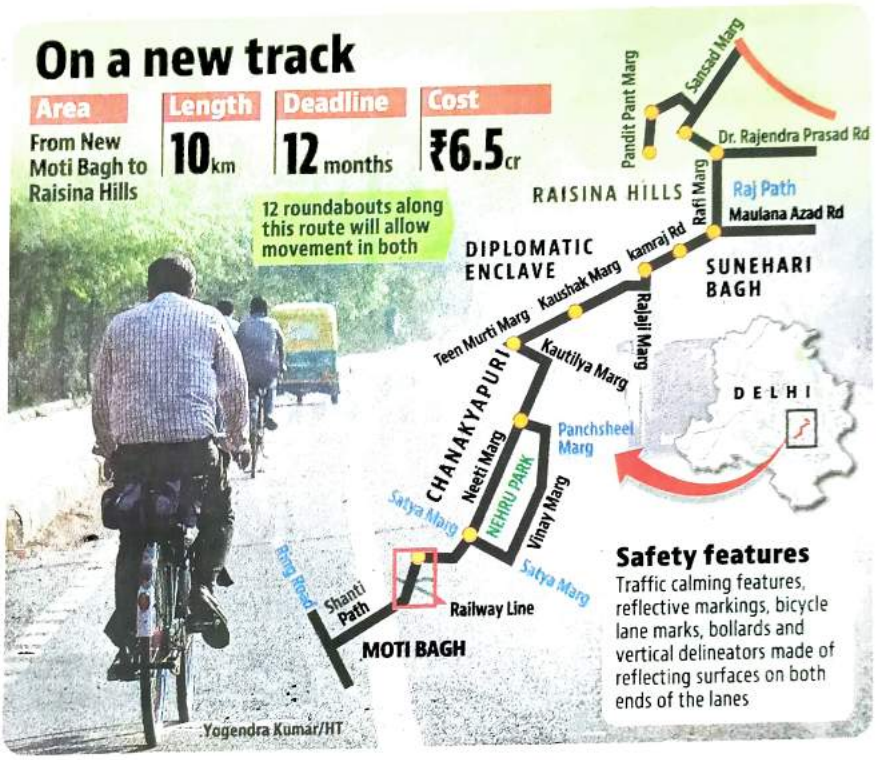

The final route approved by UTTIPEC starts from New Moti Bagh Block-C, goes to Satya Marg, covers the 2.7km periphery of Nehru Park, and then further towards Panchsheel Marg and Kautilya Marg.

In the diplomatic enclave, the track will be laid along Teen Murti Marg, Kushak Road, Rajaji Marg and Kamraj Marg along the Sunehri Bagh.

In the final phase, the track will cover Maulana Azad Road, Rafi Marg, Sansad Marg near the Parliament, and Pandit Pant Marg.

An official associated with the project said that the School of Planning and Architecture has been asked to plan the project.

The official said that UTTIPEC asked the civic body to integrate Red Cross Road, Teen Murti Marg, Rajaji Marg and Kushak Road (frequented by Common Central Secretariat employees and armed forces personnel) into the project and work in coordination with the Central Vista project near the residence of President of India, vice-president of India, and Vijay Chowk to ensure proper integration of the two projects.

> NDMC may study similar projects, such as a dedicated cycle track between Shivaji Stadium and India Gate, and incorporate the learnings into the current proposal.
>
> **UTTIPEC**

"NDMC may study similar projects implemented earlier, such as a dedicated cycle track between Shivaji Stadium and C-Hexagon (India Gate), and incorporate the learnings into the current proposal," the planning agency added, approving the project.

In October 2020, the council launched a project "Cycle4Change" under which a 5km stretch starting from Bikaner House at India Gate to Jor Bagh Metro Station via Lodhi Garden was inaugurated, an NDMC official added.

To be sure, while several dedicated bicycle lanes and cycling corridors have been operationalised in Delhi in the last decade, the utilisation of these facilities continues to remain low.

Regular cyclists say that they no longer use these tracks since they face problems of encroachment, parking and lack of maintenance.

While several government agencies are working on plans to create bicycle lanes, the lack of road safety features for pedestrians and cyclists is a major concerns for the commuters.

At least 300 cyclists have died between 2016 and 2022 in fatal accidents, according to data from a study at the Transportation Research and Injury Prevention (TRIP) Centre at Indian Institute of Technology (IIT) Delhi in November 2022.

Forty-three-year-old Sanjay Chowdhary, part of Dwarka-based cyclists group Himalayan Eagles, said that nobody uses the existing corridors because they are encroached upon, vehicles are illegally parked there, there are boulders at regular intervals, forcing riders to dismount, and are poorly maintained.

"Eventually, these cycling lanes just serve the purpose of beautification. There is no practical utility and even lane markings are faded eventually. The people who regularly cycle need large 20-30km-long routes or loops which are safe and accessible. Smaller tracks are not practical as people are forced to eventually come back to roads with heavy traffic. We hope agencies will keep practical utility in mind while executing the project," he added.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPER IV दैनिक जागरण नई दिल्ली, 27 मार्च, 2023 DATED----------

चुनौतियां बेशुमार, फिर भी देश की अर्थव्यवस्था की तेज गति बरकरार : पुरी

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली : नवंबर 2021 में जब दुनियाभर में पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे थे, तब भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तेल की कीमतें न बढ़ाने का निर्णय लिया था। जबकि उस वक्त देश में एक वर्ष से पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़े थे। इसके पीछे केंद्र सरकार का मकसद यह था कि कीमत वृद्धि का प्रभाव गरीबों की जेब पर न पड़े। देश में निश्चित रूप से चुनौतियां बड़ी हैं। इसके बावजूद हमारी अर्थव्यवस्था निरंतर प्रगति पर है। ये बातें केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने रविवार को तुगलकाबाद गांव स्थित डीडीए खेल परिसर में महिला-पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता के समापन अवसर पर मीडिया से बातचीत के दौरान कहीं।

तुगलकाबाद गांव स्थित डीडीए खेल परिसर में महिला कबड्डी टीम की कप्तानों के बीच टास उछालते केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, सांसद रमेश बिधूड़ी (सबसे बाएं) और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा (बाएं से तीसरे) ● जागरण

उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में हम दुनिया में नौवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवधा थे, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश का स्थान पांचवां है। बहुत जल्द भारत की अर्थव्यवस्था तीसरे पायदान पर पहुंच जाएगी।

कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के साथ प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष योगिता सिंह भी मौजूद थीं। केंद्रीय मंत्री पुरी ने दर्शकों के साथ पीएम मोदी के 'मन की बात' कार्यक्रम भी सुने और अपने अनुभव साझा किए।

- केंद्रीय मंत्री ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में दुनिया में भारत की अर्थव्यवस्था पांचवें नंबर पर
- पूरे विश्व में नरेन्द्र मोदी एकमात्र ऐसे नेता, जो अपने देश के नागरिकों से करते हैं सीधा संवाद

यहां की समस्याओं के निस्तारण में पुरी का योगदान : बिधूड़ी

स्थानीय सांसद रमेश बिधूड़ी ने दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र में विकास को लेकर केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी का आभार जताते हुए कहा कि उनका दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र की समस्याओं के निस्तारण में विशेष योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि आज दक्षिणी दिल्ली में चौथे फेज के मेट्रो का जो कार्य चल रहा है, वह द्वारका एरोसिटी से तुगलकाबाद तक वर्ष 2016 में शुरू होना था। इसमें 50 फीसद राज्य सरकार और 50 फीसद केंद्र सरकार का योगदान है। स्थानीय सांसद रमेश बिधूड़ी ने कहा कि मोदी सरकार की नीति के कारण देश के युवाओं में खेल के प्रति रुचि भी बढ़ी है। वह आगे बढ़ रहा है।

लाइव ही सुनता हूं 'मन की बात' : पुरी ने कहा कि यह मेरा सौभाग्य रहा है कि 'मन की बात' कार्यक्रम के 99 एपिसोड में से अधिकतर लाइव सुने हैं। कुछ एपिसोड रिकार्डिंग के माध्यम से सुनकर प्रेरणा ली है। उन्होंने कहा कि विश्व में ऐसा कोई नेता नहीं है जो अपने देश के नागरिकों के साथ सीधा संवाद करता हो। उन्होंने कहा कि आर्गन डोनेशन की बात हम सुनते आए हैं, लेकिन पीएम मोदी की इस प्रेरणा का समाज पर अलग असर होगा। महिला सशक्तीकरण हमारी संस्कृति और सभ्यता का हिस्सा है। उन्होंने गुरुनानक देव को भी याद किया। गुरुनानक देव ने भी लैंगिक असमानता की बात पांच सौ वर्ष पहले कही थी। उन्होंने कहा कि भारत में जब से नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री का दायित्व संभाला है, तब से सरकार की नीतियों और योजनाओं में भी महिला सशक्तीकरण का प्रभाव दिखता है।

महिला एवं पुरुष की 72 टीमों ने लिया हिस्सा

शनिवार को 'खेलो इंडिया' कार्यक्रम के तहत 'सांसद खेल स्पर्धा द्वितीय केस' के अंतर्गत सांसद रमेश बिधूड़ी ने विवेक बिधूड़ी फाउंडेशन के माध्यम से इस प्रतियोगिता की शुरुआत की थी। प्रतियोगिता में दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र से महिला एवं पुरुष की कुल 72 टीमों ने हिस्सा लिया। मैच के दूसरे दिन रविवार को पुरी एवं बिधूड़ी ने फाइनल मुकाबलों में विजयी टीमों को 11,000 रुपये, द्वितीय स्थान पाने वाली टीम को 7,100 रुपये एवं तृतीय स्थान पाने वाली टीम को 5,100 रुपये के चेक, ट्रॉफी और प्रमाणपत्र प्रदान किए।

। नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । सोमवार, 27 मार्च 2023

सब सिटी द्वारका का पहला एफओबी लोगों को मिला

NSUT के पास बना, स्टूडेंट्स और आसपास के लोगों को होगा फायदा

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

द्वारका में एनएसयूटी के पास पहला एफओबी तैयार हो गया है। मधु विहार का दूसरा एफओबी भी 15 अप्रैल तक तैयार होने की संभावना है। दोनों ही जगहों पर सड़क पार करने वालों की संख्या काफी अधिक होती है।

मधु विहार का एफओबी भी 15 अप्रैल तक तैयार होने की उम्मीद

एनएसयूटी (नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नॉलजी) के पास बने इस एफओबी से न सिर्फ एनएसयूटी में आने वाले स्टूडेंट्स और स्टाफ को फायदा होगा, बल्कि सुलहकुल मंदिर में जाने वाले श्रद्धालुओं को भी सुविधा होगी। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, स्टाफ और आसपास की सोसायटियों के लोग जब यहां से सड़क पार करते थे, तो ट्रैफिक स्लो हो जाता था।

सुलहकुल मंदिर में जाने वाले श्रद्धालुओं को भी सुविधा होगी

वहीं, मधु विहार में भी डीडीए एफओबी बनाने का काम तेजी से कर रहा है। अधिकारियों के अनुसार यह एफओबी भी आगामी 15 अप्रैल तक शुरू होने की उम्मीद है। यहां पर जाम की स्थिति बनी रहती है। सड़क के एक तरफ सोसायटियां हैं और दूसरी तरफ बड़ा बाजार और अस्पताल भी है।

डीडीए ने द्वारका में 2018 में चार एफओबी बनाने की बात कही थी। इनमें से दो जगहों पर काम शुरू हो गया है। लेकिन दो जगह का काम फंसा हुआ है। इनमें पहला एफओबी द्वारका कोर्ट और इंदिरा गांधी अति विशिष्ट अस्पताल के बीच बनना है। वहीं, एक अन्य एफओबी सेक्टर-1 और 7 के बीच बनना है। अधिकारियों के अनुसार दोनों जगहों पर कुछ पेड़ आ रहे हैं।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS

WWW.INDIANEXPRESS.COM
THE SUNDAY EXPRESS, MARCH 26, 2023

Plea against order on tree pruning in Vasant Vihar: HC raps MCD for non-compliance

EXPRESS NEWS SERVICE
NEW DELHI, MARCH 25

WHILE HEARING a plea against the National Green Tribunal's (NGT) order which allowed further pruning of trees in Vasant Vihar colony, alleging that approximately 800 trees have been "pruned/lopped-off", Delhi High Court pulled up the Municipal Corporation of Delhi observing that it had not complied with the court's previous orders.

A single judge bench of Justice Najmi Waziri was hearing a plea moved by Sanjeev Bagai, who had challenged a January 19 NGT order which allowed for "further pruning of the trees" to be carried out by civic authorities concerned — DDA or MCD — in strict accordance with Delhi Preservations of Trees Act, 1994, and guidelines issued by deputy conservator of forest, (HQ)/member secretary, Tree Authority, for pruning of trees under the Act.

The HC had observed on March 1 that a detailed assessment of the "activity done by the RWA needs to be carried out", further pruning in the area concerned has to be "stopped right away", and kept further pruning in the area "in abeyance".

When the matter was taken up on March 20, the high court observed that "nothing had been done by the corporation in compliance of previous orders of this court". Justice Waziri observed that remedial measures for conservation and preservation of the colony's green areas, in particular its trees, have to be initiated on an urgent basis and the same is not to anyone's detriment. The court directed MCD's zonal deputy commissioner to file an affidavit in seven days, failing which the deputy commissioner should be present in court on the next date.

Previously, the high court had appointed advocate Aditya N Prasad as amicus curiae to assess the situation at the site and assist the court. It had said Prasad will be assisted by various officials, including from police, PWD, MCD, DDA etc. It had further directed the MCD and tree officer to file extensive photos as well as a report.

The tree officer had been previously directed to file a fresh affidavit stating what was noticed at the site and "further orders, as may be necessary, too shall be issued by tree officer", the court had said.

During the hearing on March 20, Prasad had submitted that the inspection report filed by the tree officer was erroneous as it referred to damaged roots of four trees in Block A, and nine trees in Block B of Vasant Vihar Colony "because the trees have already been felled and only their stumps are remaining". Therefore, the euphemistic reference to them as "damaged" is to ignore the stark reality, Prasad said. The court looked at the photos attached to the report and said it shows the stumps being excavated from the earth and directed the tree officer to look into the matter and initiate appropriate measures within four days.

दैनिक जागरण नई दिल्ली, 26 मार्च, 2023

देश में खेल स्पर्धाओं और खिलाड़ियों में पीएम नरेन्द्र मोदी की खास दिलचस्पी : पीयूष गोयल

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली: देश में पहली बार आजादी का अमृत महोत्सव देशवासियों की ओर से उल्लास के साथ मनाया गया। देश के हर नागरिक ने हर घर तिरंगा लगाकर दुनिया को एकता का संदेश दिया। आज देश में हर जगह तिरंगा लहराता दिखता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों में राष्ट्र के प्रति देशभक्ति की भावना जाग्रत करने का काम किया है। प्रधानमंत्री मोदी युवाओं के प्रति इतने सजग हैं कि वे स्वयं अपने संसदीय क्षेत्र में खेल स्पर्धाओं का आयोजन करते हैं और उसमें सम्मिलित होते हैं। देश में खेल स्पर्धाओं और खिलाड़ियों में पीएम मोदी की खास दिलचस्पी रहती है।

ये बातें केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने तुगलकाबाद गांव स्थित डीडीए खेल परिसर में महिला-पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता के शुभारंभ के दौरान कही। खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत 'सांसद खेल स्पर्धा द्वितीय फेस' के अंतर्गत सांसद रमेश बिधूड़ी ने विवेक बिधूड़ी फाउंडेशन के माध्यम से इस प्रतियोगिता की शुरुआत की।

डीडीए खेल परिसर में सांसद खेल स्पर्धा द्वितीय फेज के तहत दो दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का उदघाटन करते केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और सांसद रमेश बिधूड़ी ● सौ. सांसद

इसमें दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र से कुल 72 महिला एवं पुरुष की टीमों ने भाग लिया। इस मुकाबले में प्रथम विजेता टीम को 11000 रुपये, द्वितीय स्थान पाने वाली टीम को 7100 रुपये एवं तृतीय स्थान पाने वाली टीम को 5100 रुपये नकद राशि प्रदान कर पुरस्कृत किया जाएगा।

स्थानीय सांसद रमेश बिधूड़ी ने कहा दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र में वर्ष 2021 से रन फार यूनिटी, क्रिकेट, वालीबाल, खो-खो आदि प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। युवाओं में खेल के प्रति रुचि का स्तर बढ़ा है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष 2022 में 23 व 24 मार्च को आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता, जिसमें 59 टीमों ने भाग लिया था। आज इस प्रतियोगिता में दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र से 72 टीमों ने भाग लिया है। इस अवसर पर बिधूड़ी ने कबड्डी देखने आए दर्शकों को बताया कि 26 मार्च को प्रतियोगिता का समापन और प्रधानमंत्री के 'मन की बात' कार्यक्रम भी है। यह कार्यक्रम हर माह के अंतिम रविवार को प्रातः 11 बजे से 11.30 बजे तक सुना जाता है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
SATURDAY, MARCH 25, 2023
S----------DATED----------

DDA's luxury flats in Dwarka to be up for bidding by Diwali

Vibha.Sharma@timesgroup.com

New Delhi: The Delhi Development Authority is likely to complete by Diwali the work on a luxury-flat scheme in southwest Delhi's Dwarka.

The project site is located at Sector 19B. "We are making our best efforts to complete the project by November. Thereafter, applications will be invited from buyers and a computerised draw of lots conducted. While the prices for these luxury flats are yet to be determined by the finance department, the authority will add premium charges on them because of their location and facilities available," the official added.

The high-end accommodation will feature, for the first time, penthouses with terrace gardens and luxe furnishing. There will also be super-HIG, HIG and MIG flats.

"This will be DDA's first residential complex with only luxury flats. There will be 1,114 luxury flats of which 14 will be penthouses, 168 super-HIG and 932 HIG flats. In total, there will be 11 residential towers, of which seven will have two penthouses each," the official said.

The penthouses will be fully furnished duplexes with terrace gardens, luxe fittings and four bedrooms each with attached bathrooms and other amenities. The super-HIG flats will have three bedrooms each with attached bathrooms and servant quarters. In building the flats, DDA has gone for the green building concept, with solar heating, organic waste disposal and energy efficient lighting.

Apart from Dwarka, DDA will also offer around 400 HIG and MIG flats in Jasola, which, the authority believes, will be much sought after due to their location. "There would be 170 HIG flats and we plan to invite applications on them before the Dwarka 19B project," the official said. As of now, there are around 40,000 vacant units available with DDA, mostly in Narela. "Majority of them are LIG and EWS flats and we are making all efforts to sell them," the official added.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

27 मार्च • 2023 सहारा

नगर निगम व डीडीए ने गांवों को बर्बाद किया : सोलंकी

■ नई दिल्ली (एसएनबी)।

■ कहीं न कहीं राजनीति गांव के साथ हुई है और 1984 के बाद दिल्ली के अंदर पंचायत के चुनाव ही बंद कर दिए गए

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय मे राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान द्वारा आयोजित नेशनल कांफ्रेंस ऑन लोकल गवर्नेंस इन इंडिया 75 फोरम पर बोलते हुए पालम 360 के प्रधान चौधरी सुरेंद्र सोलंकी ने कहा कि दिल्ली नगर निगम और जीडीए ने मिलकर दिल्ली के गांवों को बर्बाद कर दिया है। आज तक की जितनी भी सरकारें रही, कहीं ना कही उन सब का हाथ इसके अंदर रहा है। कहीं न कहीं राजनीति गांव के साथ हुई है और 1984 के बाद दिल्ली के अंदर पंचायत के चुनाव ही बंद कर दिए गए। जबकि भारत के अंदर पंचायती राज व्यवस्था का जो मॉडल है उसका उदाहरण पूरे विदेशों में दिया जाता है। मगर हैरानी की बात है कि देश की राजधानी के अंदर ही पंचायती राज व्यवस्था से लोग वंचित है।

सोलंकी ने कहा कि केंद्र व दिल्ली सरकार से उनकी मांग है कि राजधानी में दुबारा से पंचायती राज सिस्टम चालू हो और 1963 से लेकर आज तक 225 गांव को शहरीकृत गांव घोषित किया है, जिनको नाम मात्र सुविधा दी गई है शहरीकृत के नाम पर सिर्फ जल बोर्ड की लाइनें डाली गई है।

इसके अलावा बिल्डिंग बाइलॉज भी जिस तरीके से इन्होंने लागू किया उसमें भी भ्रष्टाचार की शिकायतें है। हकीकत ये है कि दिल्ली देहात के गांव ने हमेशा दिल्ली के विकास के लिए अपनी भूमिका अदा की है। चाहे वह जमीन देने के माध्यम से लेकर हर तरीके से सहयोग करने की बात हो, हमने किया है।

मगर गांव के मूल निवासियों की उपेक्षा ही हुई है लेकिन अब ये बर्दाश्त नही होगा। बिल्डिंग बायलॉज के नाम पर जिस तरीके से मकान लाल डोरे के अंदर भी बनाए जाते है और उसमें नगर निगम वसूली करता है। जिस तरीके से शहरीकृत के नाम पर सीवर लाईनें ही डाली गई है और वह भी छोटी लाइनें डाली गई है। उसके साथ साथ जो पानी की लाइन डाली गई है, वह सीवर की लाइनें सब जगह उफान मारती है जिससे बारिश के समय में गांवों की हालत बद से बदतर हो जाती है। पीने के पानी के साथ सीवर की लाइन का पानी मिक्स होकर आता जिससे लाखों लोगों को बीमारियां हो रही है और जानें भी जा रही है।

millenniumpost
SATURDAY, 25 MARCH, 2023 | NEW DELHI

DDA WARNS ABOUT FAKE URL BEING USED IN NAME OF HOUSING SCHEME

NEW DELHI: The Delhi Development Authority on Thursday cautioned that some fraudulent people were using a fake URL in the name of its housing scheme to lure public. In a statement, the Delhi Development Authority (DDA) said it has has taken a serious view in this matter, and complaints have been lodged in the Economic Offences Wing and Cyber Crime cell of the Delhi Police. "It has come to DDA's notice that some fraudulent persons are using fake URL (https://DDAflat.org.in/index.php) in the name of DDA's Housing Scheme to lure public for booking of flats," it said.

पंजाब केसरी DELHI 26 मार्च, 2023 ▸ रविवार

खेलो इंडिया: युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है: पीयूष गोयल

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): दक्षिणी दिल्ली संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री की प्रेरणा से खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत सांसद खेल स्पर्धा द्वितीय फेस के अंतगर्त सांसद रमेश बिधूड़ी ने विवेक बिधूड़ी फाउंडेशन के माध्यम से 25 मार्च से दो दिवसीय महिला-पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन तुगलकाबाद गांव स्थित डीडीए खेल परिसर में करवाया। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ केन्द्रीय मंत्री वाणिज्य और उद्योग पीयूष गोयल द्वारा किया गया। प्रतियोगिता में दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र से कुल 72 महिला एवं पुरुष की टीमों ने भाग लिया। इस दौरान दक्षिणी दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों से हजारों की संख्या में लोग कबड्डी के रोमांचक मुकाबले देखने पहुंचे। इस अवसर पर पीयूष गोयल ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में खेलो इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत हर गरीब कमजोर वर्ग से युवाओं को बगैर आर्थिक समस्या के अपनी प्रतिभा को निखारने व आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है और खले प्रति युवाओं में अधिक रुचि देखने को मिल रही है। इस दौरान सांसद रमेश बिधूड़ी ने कहा कि पीएम मोदी ने देश में खेलों के विकास व प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आर्थिक परेशानियों के बिना आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम खेलो इंडिया की शुरुआत की। इसके तहत संसदीय क्षेत्रों में सांसद खेल स्पर्धा के अंतगर्त खेलों के आयोजन करवाने का आग्रह किया। वह अपने गांव, जिले और राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं। खेलों के प्रति रुचि का स्तर बढ़ा है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

THE HINDU Sunday, March 26, 2023 DELHI DATED

The death of the much sought-after *barsati*

Alisha Dutta
NEW DELHI

Ruchika Mehra, 24, a news researcher, recalls hearing her mother, Aradhana Mehra, 49, speak fondly about the *barsati* she had rented in Delhi's Lajpat Nagar way back in 1997. Her nostalgic stories painted pictures of barbecue nights, jam sessions, and early morning *chai* on the terrace. The two-room set was just right for someone starting out in life and single in the city, as Ms. Mehra's mother was, in an architecture firm. It worked from both an economic and strategic perspective: people could stay in a tony south Delhi neighbourhood at a pocket-permitting rent.

But when Ms. Mehra herself moved from Lucknow to Delhi in November 2022, she found that renting one was now either a luxury or a liability, as *barsatis* themselves were. They were either too expensive, with rents touching ₹80,000 or they were affordable at about ₹10,000, but with seepage, cockroaches, and dodgy house owners.

"Twenty years ago, we would deal in 20 to 30 *barsatis* a year; now we find five or six," says Siddharth Gargi, a real estate agent in Nizamuddin East, a stone's throw away from the 16th century Humayun's Tomb, a UNESCO World Heritage Centre.

The *barsati*, borrowed from the Urdu word *barsat* (heavy rain), is a room built on the terrace of an independent bungalow. "*Barsatis* occupied almost a third of the terrace. They started out as rooms for storage and sometimes as quarters for help," says Ranjan Choubey, a real estate agent with about 30 years of experience, working out of Jangpura, an area that still has low-rise homes. In time, especially in the '80s and '90s, they morphed into cool city pads, when the Delhi skyline was not dominated by concrete.

Once home to authors and artists like Amitav Ghosh, Arundhati Roy, William Dalrymple, and M.F. Husain, *barsatis* in Delhi are a rare sight now.

Humble abode: The *barsatis* that do exist are either boutique studio apartments or illegal constructions. SUSHIL KUMAR VERMA

Building by-laws

This is primarily because of a change in the Delhi Development Authority's (DDA) housing by-laws in 2013 which allowed houses to construct four floors from the earlier two floors. In 2014, the Urban Development ministry increased the floor area ratio (FAR: the measurement of a home's floor area to the size of the plot) from 150% to 200% on 750-1,000 square metre plots and from 120% to 200% for plots of 1,000 square metres and above.

Rental returns

Real estate companies entered with redevelopment plans. Mr. Gargi, who has been in the business for two decades now, says house owners collaborated with builders to remodel their two-storey houses to three- or four-storey buildings. "This would allow them to have one extra floor even after giving one floor to the builders. They would also benefit in terms of rental returns, as in comparison to *barsatis*, apartments would have much higher rents," he added.

A senior DDA official said building *barsatis* are now deemed illegal. However, the DDA's building by-laws remain silent on the *barsatis* that are already in place. Taking advantage of this 'grey area', Mr. Gargi said many builders now use temporary structures to build a room on the terrace, which can be assembled and dismantled in a couple of days.

"These house owners then turn such space into boutique rooms and rent it out for more than ₹40,000 in localities like Defence Colony, Green Park and Nizamuddin East," added Mr. Gargi.

'Bypassing laws'

Homes built mostly in post-Partition allocated land - Green Park, Greater Kailash, Defence Colony, Lajpat Nagar, Nizamuddin East - were suddenly not accessible to the upwardly mobile migrants.

The *barsatis* that do exist are either boutique studio apartments or illegal constructions, sometimes atop DDA flats or in Delhi's urban villages where buildings seem to run into each other.

"Considering the legality of *barsatis* in South Delhi continue to remain a grey area, many house owners have tried benefitting from it by building modular temporary rooms on the top of the terrace as they bypass the jurisdiction of the DDA," says a senior lawyer.

However, areas like Khirki Extension, some parts of Jangpura and Kotla that fall under the Lal Dora land, do not fall under the DDA laws. Builders don't have to adhere to building by-laws, he added. So, *barsatis* today are in the more congested parts of town.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS पंजाब केसरी DELHI · 25 मार्च, 2023 ▶ शनिवार

हम एलजी के साथ लड़ना नहीं, मिलकर काम करना चाहते हैं: केजरीवाल

उपराज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव का सीएम ने किया समर्थन

- एलजी की तमाम अड़चनों के बावजूद 'आप' की सरकार ने शानदार काम किए: केजरीवाल
- सीएम और एलजी जब एक साथ काम करें तो यह होगी असली डबल इंजन की सरकार

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी) : हम एलजी से लड़ना नहीं चाहते हैं, उनके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। यह बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र में शुक्रवार को पांचवें दिन कही। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में चल रहे बजट सत्र में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि एलजी की तमाम अड़चनों के बाद भी हमारी सरकार ने बहुत शानदार काम किया है। मुख्यमंत्री ने एलजी के अभिभाषण का जिक्र करते हुए कहा कि एलजी साहब ने अपने अभिभाषण में कहा कि मेरी सरकार ने शिक्षा-स्वास्थ्य में खूब काम किया। आजादी के बाद सबसे ज्यादा विकास हमारी सरकार ने किया। ऐसा बोलते हुए उनका सीना भी गर्व से चौड़ा हुआ। मैं एलजी साहब से कहना चाहता हूं कि अगर आप हमारे कामों में टांग न अड़ाएं तो हम आपको सीना चौड़ा करने के और मौके देंगे।

केजरीवाल ने एलजी से अपील करते हुए कहा कि आप गुजरात से आए हैं। आप हमारे मेहमान हैं। एलजी को दिल्ली के बारे में कुछ नहीं पता है। मुझे नहीं लगता कि एलजी को दिल्ली की 70 विधानसभाओं और दिल्ली की कुछ सड़कों के नाम भी पता होंगे। मैं एलजी से कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा मिलकर काम करिए। हम भी आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। आने वाली पीढ़ियां क्या कहेगी कि ये आपस में लड़ रहे थे? अभी हमें बहुत काम करने हैं। हमें यमुना साफ करनी है, पूरी दिल्ली में सीवर की पाइपलाइन डालनी है, घर-घर सीवर लेकर जाने हैं, पानी की पाइप लाइन, नए-नए एसटीपी और ट्यूबवेल लगाने हैं, बसें खरीदनी हैं, प्रदूषण ठीक करना है, ट्रैफिक ठीक करना है। काम की कमी नहीं है। हम मिलकर काम करते हैं न। एलजी हमसे लड़ते क्यों हैं? कानून-व्यवस्था में हमारी मदद लें। कानून व्वयवस्था में हम आपके साथ मिलकर काम करेंगे। इससे दिल्ली सुरक्षित होगी। यह हिंदुस्तान-पाकिस्तान नहीं है। डीडीए में साथ मिलकर काम कर सकते हैं। ये डबल इंजन इंजन की सरकार बात कहते हैं। जिस दिन दिल्ली के सीएम और एलजी ने मिलकर काम करना शुरू कर दिया। यही असली डबल इंजन की सरकार होगी।

विधानसभा में बोलते अरविंद केजरीवाल।

हमारे कामों में टांग न अड़ाएं तो हम आपको सीना चौड़ा करने के और मौके देंगे: सीएम

मुख्यमंत्री ने कहा कि अभिभाषण को पढ़ते हुए एलजी साहब का सीना भी थोड़ा सा चौड़ा हो रहा था। वो कह रहे थे कि मेरी सरकार बहुत पारदर्शी अच्छी है। आजादी के बाद से अब तक सबसे अच्छा काम मेरी सरकार ने किया है। मेरी सरकार ने सभी क्षेत्रों में बहुत अदभुत विकास किया। उन्होंने अपने अभिभाषण में शिक्षा-स्वास्थ्य समेत एक-एक क्षेत्र गिनाए कि किस में कितना विकास हुआ। मैं उपराज्यपाल से कहना चाहता हूं कि अगर आप हमारे कामों में टांग न अड़ाएं तो हम आपको सीना चौड़ा करने के और मौके देंगे। हम ये रोज-रोज की खींचतान नहीं चाहते हैं। हम काम आपके साथ मिलकर करना चाहते हैं।

असली काम हमारे शिक्षकों ने किया

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अदभुत काम हुआ। हम सबने मिलकर एक फैसिलिटेटर की तरह काम किया है। असली काम तो हमारे शिक्षकों और प्रधानाचार्यों ने किया है। उन्होंने बच्चों के साथ कड़ी मेहनत की है। इन शिक्षकों के अंदर यह जज्बा तब आया जब हमने उन्हें प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजा। दिल्ली के शिक्षक ट्रेनिंग के लिए सिंगापुर, फिनलैंड, कनाडा और कई जगह गए। वे जब वापस लौटकर आए और उन्हें विदेश में जो एक्सपोजर मिला, वो बहुत ही शानदार था। अभी तक दिल्ली के करीब 1100-1200 शिक्षक-प्रधानाचार्य विदेशों में ट्रेनिंग लेकर आ चुके हैं। एलजी की तमाम अड़चनों के बावजूद हमने इतना अच्छा काम किया है।

डीडीसीडी के दफ्तर पर ताला लगा दिया

सीएम ने कहा कि हमने दिल्ली डायलॉग एड डेवलपमेंट कमीशन (डीडीसीडी) बनाया। दिल्ली में मोटे तौर पर जितने भी बडे काम किए हैं, उन सारी योजनाओं पर रिसर्च और फाइनल पॉलिसी ड्राफ्ट बनाने का काम डीडीसीडी में होता है। दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, फेसलेस सर्विसेज पॉलिसी और डोर-स्टेप डिलीवरी पॉलिसी समेत कई योजनाए पर डीडीसीडी ने पॉलिसी बनाई। एक दिन अचानक एलजी ने एसडीएम भेजकर डीडीसीडी के वाइस चेयरमैन जस्मीन शाह के दफ्तर को सील कराकर ताला लगवा दिया। इस तरह के काम कौन करता है? संवैधानिक पद पर बैठा कोई आदमी इस तरह के काम करे तो शोभा नहीं देता है। छह महीने से डीडीसीडी का दफ्तर बंद है।